

## डीरेगुलेशन एवं संवृद्धि हेतु भारत की रणनीति

### प्रलम्बित के लिये:

[GDP](#), [मुद्रास्फीति](#), [बेरोजगारी](#), [कोविड-19 महामारी](#), [वशिव बैंक](#), [चालू खाता घाटा](#), [अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष](#), [वनिविश](#), [उत्पादन-लकिड प्रोत्साहन \(PLI\) योजना](#), [बौद्धिक संपदा अधिकार](#)।

### मेन्स के लिये:

सतत आर्थिक विकास हेतु प्रमुख क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अवसर एवं चुनौतियाँ

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. वी. अनंथा नागेश्वरन ने घोषणा की है कि वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में डीरेगुलेशन प्रमुख विषय होगा।

- यह घोषणा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) की उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रतबंधात्मक नियमों को आसान बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

**नोट:** डीरेगुलेशन का आशय उद्योगों या संबंधित क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया से है ताकि इसमें नए हतिधारकों के प्रवेश को प्रोत्साहित करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के साथ बाजार की दक्षता में वृद्धि की जा सके।

- यह वर्ष 1991 के बाद शुरू किये गए आर्थिक सुधारों (LPG सुधार) का एक प्रमुख पहलू रहा है, जिससे देश अत्यधिक वनियमित एवं राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अधिक उदार तथा वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुआ है।
- उदाहरण के लिये वर्ष 1978 में भारत ने एयरलाइन वनियमन अधिनियम पारित किया, जिसके तहत एयरलाइन कंपनियों को अधिक नियंत्रण प्रदान किया गया जिससे इस उद्योग के परिदृश्य में बदलाव आया।

## भारत की आर्थिक संवृद्धि हेतु प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र कौन से हैं?

- संवृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में डीरेगुलेशन: वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य एवं स्थानीय स्तर पर डीरेगुलेशन को संवृद्धि के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में रेखांकित किया गया है।
- महिलाओं के लिये "जोखमिपूरण" माने जाने वाले 118 व्यवसायों पर लगे पुराने प्रतिबंधों का हवाला देते हुए महिला श्रम शक्ति भागीदारी में सुधार लाने तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के क्रम में अधिक आर्थिक संभावनाओं के अवसर खोलने का आह्वान किया गया है।
- वेतन वृद्धि एवं उपभोग: CEA द्वारा वेतन स्थिरता पर प्रकाश डाला गया। इसमें विशेष रूप से संविदा कर्मचारियों पर बल दिया गया, जिनकी मुद्रास्फीति के साथ तालमेल रखने में विफलता के कारण कर्य शक्ति सीमित हो रही है। इसके साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि के बावजूद, वेतन असमानता बनी हुई है।
  - आय को जीवन-यापन लागत के अनुरूप करने तथा मांग एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के क्रम में कॉर्पोरेट वेतन संरचना में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- कार्यबल का अनौपचारिकीकरण: कोविड-19 महामारी ने नियमित रोजगार से अनौपचारिक रोजगार की ओर बदलाव को तेज कर दिया है, जिससे रोजगार की सुरक्षा और लाभ कमजोर हो गए हैं। कंपनियों के लिये फायदेमंद होने के बावजूद, यह प्रवृत्ति श्रमिकों की बचत और निवेश करने की क्षमता को सीमित करके उपभोग एवं आर्थिक विकास को बाधित करती है।
- लघु एवं मध्यम उद्यम (SME): भारत का लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्र आर्थिक वृद्धि के लिये महत्वपूर्ण है, मूलतः वनियमित क्षेत्र

- में। हालाँकि इसे "सूक्ष्म" श्रेणी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे संसाधनों और सहायता तक पहुँच सीमिति हो जाती है।
  - जर्मनी और स्वटिज़रलैंड से सबक लेते हुए भारत को SME में वृद्धि करनी चाहिये। एक जीवित SME क्षेत्र भारत के वनिरिमाण से सकल घरेलू उत्पाद में 25% भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।
- **रोज़गार सृजन और श्रम शक्ति भागीदारी:** भारत को अपने बढ़ते कार्यबल को समायोजित करने के लिये वार्षिक रूप से लगभग 8 मिलियन रोज़गार सृजन की आवश्यकता है। CEA ने पूंजी और श्रम-गहन विकास के बीच संतुलन बनाने पर बल दिया, जिसमें नज़िी क्षेत्र की अहम भूमिका होगी।
  - पहली बार नौकरी पर रखे गए लोगों के लिये नकद प्रोत्साहन और भवषिय नधिियोगदान जैसी नीतियों का उद्देश्य रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है।

## भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये डीरेगुलेशन के क्या नहितार्थ हैं?

- **नज़िी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा:** डीरेगुलेशन में सुस्तता से व्यवसायों को अधिक स्वायत्तता के साथ कार्य करने, नौकरशाही में वलिंब को कम करने और तेज़ी से नरिणय लेने में सहायता मिलती है। इससे दूरसंचार, वमिानन और आईटी जैसे उद्योगों का विकास हुआ है।
- **नवप्रवर्तन और उद्यमिता:** डीरेगुलेशन में सुस्तता से अनुपालन बोझ में कमी आई है, व्यवसाय को आसान बनाने में सहायता मिली है, जिससे स्टार्टअप और नवप्रवर्तन के लिये अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।
  - डीरेगुलेशन के कारण उद्योगों के विकास के साथ-साथ वभिनिन क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में भी वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान मिला है।
- **वदिशी नविश का आकर्षण:** वभिनिन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष वदिशी नविश (FDI) पर प्रतबिंध हटाकर, डीरेगुलेशन में ढील देने से भारत को वैश्विक नविशकों के लिये एक पसंदीदा गंतव्य बनने में सहायता मिली है, जिससे पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में वृद्धि हुई है।
- **दक्षता वृद्धि और प्रतसिपर्द्धा:** एक वनियमन-मुक्त बाज़ार स्वस्थ प्रतसिपर्द्धा को बढ़ावा देता है, प्रतसिपर्द्धी मूल्यों परबेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को सुनश्चित करता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

## LPG (उदारीकरण, नज़िीकरण, वैश्वीकरण) सुधार

- प्रधानमंत्री राव ने वतित मंत्री मनमोहन सहि के साथ मलिकर **LPG सुधारों (उदारीकरण, नज़िीकरण और वैश्वीकरण) की** शुरुआत की, जिन्हें संकट से उबरने और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत की आर्थिक रणनीति की आधारशला के रूप में प्रस्तुत किया गया।
  - **उदारीकरण:**
    - **नवीन व्यापार नीति:** लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार करके और गैर-आवश्यक आयातों को नरियात से जोड़कर नरियात को बढ़ावा देने के लिये आरंभ की गई।
    - **एक्जमि स्क्रिप्स (Exim Scrips):** सरकार ने नरियात सब्सिडी हटा दी और इसके बजाय नरियातकों के लिये नरियात के मूल्य के आधार पर व्यापार योग्य एक्जमि स्क्रिप्स की शुरुआत की। इस नीति ने आयात पर सरकारी स्वामित्व वाली फर्मा के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे नज़िी क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से माल आयात करने में सक्षम बनाया गया।
    - **लाइसेंस राज का अंत:** नवीन औद्योगिक नीति ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, एकाधिकार और प्रतबिंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रावधानों में ढील प्रदान की ताकि व्यापार पुनर्र्गठन और वलिय को सुवधाजनक बनाया जा सके। इस नीति ने नविश के स्तर की परवाह किये बगैर 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी के लिये औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया।
  - **नज़िीकरण:**
    - **FDI संबंधी सुधार:** प्रत्यक्ष वदिशी नविश (FDI) के लिये 51% तक की स्वचालित स्वीकृति आरंभ की गई, जबकि पहिले यह सीमा 40% थी।
    - **सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार पर प्रतबिंध:** सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों तक सीमिति किया गया।
    - **बाज़ार खोलना:** इन परिवर्तनों से भारत में व्यापार करना आसान हो गया, जिससे बाद के वर्षों में वदिशी वस्तुओं और नविशों में वृद्धि हुई।
- **वैश्वीकरण:**
  - **आर्थिक नीतियाँ:** इन सुधारों का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाज़ार के साथ एकीकृत करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नविश को प्रोत्साहित करना था।
  - **नरियात का अभिवर्द्धन:** भारतीय रुपए के वसितृत अवमूल्यन और नई व्यापार नीतियों के फलस्वरूप भारतीय नरियात वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतसिपर्द्धी हो गया।

## भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये डीरेगुलेशन का क्या महत्त्व है?

- **आर्थिक विकास का पुनरुत्थान:**
  - कोवडि-19 महामारी से 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था का गंभीर संकुचन शुरू हुआ। हालाँकि 2021 में GDP में 9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई कति यह जुलाई-सितंबर वतित वर्ष 25 में घटकर 5.4% हो गई है, जो RBI के 7% अनुमान से नीचे है।
  - **नौकरशाही संबंधी बाधाओं** को कम कर और बाज़ार की शक्तियों को सशक्त बनाकर, डीरेगुलेशन से उद्यमशीलता, नविश और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, जिससे संधारणीय आर्थिक सुधार एवं विकास को बढ़ावा मिलता है।

- बेरोज़गारी और अल्परोज़गार की समस्या का समाधान:
  - अप्रैल से जुलाई 2020 की अवधि में 1.8 करोड़ से अधिक बेरोज़गारों का ह्रास हुआ जिससे महामारी के कारण बेरोज़गारी की स्थिति और गंभीर हो गई।
  - व्यावसाय को सुकर बनाकर और नज़ी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देकर डीरेगुलेशन से रोज़गार के अवसर सर्जित होते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का पुनरुत्थान:
  - हाल में हुई नगण्य वृद्धि के बावजूद, कृषि क्षेत्र का, जिससे 50% से अधिक कार्यबल के रोज़गार का स्रोत, समग्र आर्थिक विकास के साथ तालमेल नहीं बन पाया है।
  - सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 1990-91 में 35% था जो वित्त वर्ष 23 में घटकर 15% हो गया है और इसकी वृद्धि दर 2022-23 में 4.7% से घटकर 2023-24 में 1.4% हो गई है।
- बुनियादी ढाँचे के अभाव की पूर्ति:
  - विश्व बैंक के अनुसार, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा में बुनियादी ढाँचे के गंभीर अभाव के साथ भारत में बुनियादी ढाँचे के अभाव का अनुमान 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - नज़ी निवेश भी कम बना हुआ है, जो 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 19.6% रहा और वित्त वर्ष 2020-21 में सकल स्थिर पूंजी निर्रमाण (GFCF) में 14.5% की गिरावट आई।
- निर्र्यात प्रतस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि और भू-राजनीतिक तनाव:
  - रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनीतिक तनावों से वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है, जिसका प्रभाव वस्तु और जूते जैसे क्षेत्रों पर पड़ा है, जहाँ निर्र्यात में कमी आई है।
  - इसके अतिरिक्त, विश्वव्यापी उद्योग बनने की अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के बावजूद, भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थता के कारण वैश्विक वृद्धि में पछिड़ गया है।

## MSME क्षेत्र

- परिचय:
  - MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) वे व्यवसाय हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण और संरक्षण में शामिल हैं।
- वर्गीकरण:
  - इन्हें वर्गीकरण हेतु संयंत्र और मशीनरी या सेवा उद्यमों के लिये उपकरणों में निवेश के साथ-साथ उनके वार्षिक आवर्त के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

CLASSIFICATION	MICRO	SMALL	MEDIUM
Manufacturing Enterprises and Enterprises rendering Services	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.1 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 5 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.10 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 50 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.50 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 250 crore

- भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान:
  - रोज़गार, नवाचार, निर्र्यात और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के साथ MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 45%, निर्र्यात में 40% तथा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 37.54% है।
  - MSME के अंतर्गत निर्रमाण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 7.09% का योगदान है, जबकि सेवा क्षेत्र में इसका योगदान 30.50% है।

## भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तेज़ी लाने के लिये प्रमुख पहल क्या हैं?

- [नई आर्थिक नीति \(NEP\), 2020](#)
- [रणनीतिक निवेश](#)
- [व्यापक श्रम संहिता](#)
- [उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन \(PLI\) योजना](#)
- [पीएम गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान](#)
- [भारतमाला परियोजना](#)
- [सटार्ट-अप इंडिया](#)
- [मेक इन इंडिया 2.0](#)

## डीरेगुलेशन को प्रभावी बनाने हेतु भारत क्या रणनीति अपना सकता है?

- **PPP और प्रतस्पर्द्धा को प्रोत्साहति करना:**
  - डीरेगुलेशन को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु सरकार एवं नजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि संबंधित सुधारों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किये जाने के साथ एकाधिकार को समाप्त करने एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिये नष्टिपक्ष प्रतस्पर्द्धा को प्रोत्साहति कयिा जा सके ।
- **प्रोद्योगिकी का लाभ उठाने के साथ अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना:**
  - शासन में पारदर्शति बढ़ाने, अनुपालन बोझ को कम करने तथा अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थति करने के क्रम में **डजिटल प्लेटफॉर्म का** उपयोग करना चाहयिे । **डजिटल इंडयिा पहल** एवं व्यवसाय करने में सुलभता के तहत सगिल-वडिो अनुमोदन प्रणाली को लागू कयिा जाना चाहयिे ।
- **वत्तितीय समावेशन को बढ़ावा तथा SME को समर्थन देना:**
  - बैंकगि एवं ऋण सुवधाओं तक पहुँच बढ़ाकर हाशयि पर स्थति समुदायों पर धयान दयिा जाना चाहयिे । इसके साथ ही SME को बाज़ार की गतशीलता के अनुकूल बनाना चाहयिे । **उदाहरण: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) और स्टार्टअप इंडयिा पहल ।**
- **वैश्वकि उदाहरणों से सीखना:**
  - स्थानीय संदर्भों के अनुसार वैश्वकि स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने एवं वशिवास नरिमाण के क्रम में **सहभागी नरिणय प्रक्रियाओं में हतिधारकों** को शामिल करने की आवश्यकता है ।
  - **सगिापुर में डीरेगुलेशन** से न केवल आर्थकि वकिास को बढ़ावा मलिा है बल्क वत्तितीय क्षेत्र, दूरसंचार, परविहन एवं वदियुत क्षेत्र में सुधार होने से जीवन स्तर उन्नत हुआ है ।
- **क्षेत्र-वशिषिट सुधार:** क्षेत्र-वशिषिट सुधारों के तहत वत्ति, पर्यावरण एवं रक्षा जैसे परमुख क्षेत्रों में **मज़बूत नयामक नगिरानी सुनिश्चिति करते हुए अद्वत्तीय चुनौतयिों के समाधान** पर बल देना चाहयिे ।
  - उदाहरण के लयिे **रक्षा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमतदेना, आधुनकिीकरण को बढ़ावा देने** के अनुरूप है लेकनि इसमें सुरक्षा हेतु कड़े नयिमों की भी आवश्यकता है जबकि **दविला और शोधन अक्षमता संहति (IBC)** जवाबदेहति बनाए रखने के साथ जोखमिों को कम करते हुए वत्तितीय समाधान को सुव्यवस्थति करने पर केंद्रति है ।

दृषटिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

भारत की उभरती अर्थव्यवस्था से संबंधति चुनौतयिों एवं अवसरों पर चर्चा करते हुए सतत एवं समावेशी वकिास सुनिश्चिति करने हेतु परमुख क्षेत्रों की भूमकिा पर प्रकाश डालयिे ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

**प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयिे: (2018)**

1. एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी नरिमाण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रयिा के रूप में की जा सकती है, जो कसिी देश के व्यक्तयिों को अधिक पूंजी संचय करने में सक्षम बनाती है ।
2. कसिी देश के व्यक्तअधिकि पूंजी का संचय कर पाते हैं ।
3. देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है ।
4. गोचर धन का संचय हो पाता है ।
5. अगोचर धन का संचय हो पाता है ।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 2 और 4
- (d) 1, 3 और 4

उत्तर: (c)

**प्रश्न: प्रच्छन्न बेरोज़गारी का सामान्य अर्थ होता है, क(2013)**

- (a) लोग बड़ी संख्या में बेरोज़गार रहते हैं ।
- (b) वैकल्पकि रोज़गार उपलब्ध नहीं है ।
- (c) श्रमकि की सीमांत उत्पादकता शून्य है ।
- (d) श्रमकिों की उत्पादकता नमिन है ।

उत्तर: (c)

**??????:**

**Q.** भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-strategy-for-deregulation-and-growth>

